बुधवार
02 सितम्बर 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 221
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दूनवैलीमेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

शहीद राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा: धामी

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों का बलिदान प्रत्येक उत्तराखंडवासी की स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल झूलाघर, मसूरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।उ मुख्यमंत्री ने मसूरी गोलीकांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने अपने संघर्ष, तप, त्याग और बलिदान से उत्तराखंड राज्य गठन के सपने को साकार किया है। उन्होंने कहा कि मसूरी की धरती उत्तराखंड के संघर्ष और बलिदान की साक्षी है। वर्ष 1994 में मसूरी में हजारों राज्य आंदोलनकारी खटीमा गोलीकांड के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी आंखों में आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य का सपना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों का बलिदान प्रत्येक उत्तराखंडवासी की स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा। उन्होंने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हम इन बलिदानों को कभी नहीं भूलेंगे। नई पीढ़ी को भी राज्य निर्माण के संघर्ष से परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य

आंदोलन में मातृशक्ति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी माताओं-बहनों ने अपने संघर्ष और सहभागिता से आंदोलन को मजबूती प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की पहचान और गौरव के आधार हैं। राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों की मासिक पेंशन घ्3 हजार से बढ़ाकर 5,500 की गई है। जेल गए और घायल आंदोलनकारियों की पेंशन 6 हजार से बढ़ाकर 7 हजार तथा सक्रिय आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 से बढ़ाकर 5,500 प्रतिमाह की गई है। पूर्णत: शय्याग्रस्त दिव्यांग राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन भी 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार प्रतिमाह की गई है। राज्य आंदोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चों को स्कूल और कॉलेज में नि:शुल्क शिक्षा तथा आंदोलनकारियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त नकल विरोधी कानून और कठोर भू-कानून लागू करने जैसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं। बीते पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता और डेमोग्राफी की रक्षा के लिए धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून भी लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि की शांति और संस्कृति के खिलाफ काम करने वाली हर मानसिकता पर सख्ती से कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य के सीमांत क्षेत्रों तक सड़क, रेल, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ है। राज्य में चारधाम यात्रा और धार्मिक पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है। युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट ध्येय है कि उत्तराखंड का कोई भी युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर न हो, कोई भी गांव विकास से वंचित न रहे तथा देवभूमि की अस्मिता सदैव सुरक्षित और समृद्ध बनी रहे।

उन्होंने कहा कि हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, हर गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध बने, हर हाथ को काम और हर युवा को रोजगार मिले। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी श्रीमती मीरा सकलानी, रविन्द्र जुगरान, जिलाधिकारी देहरादून आशीष चौहान सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

सूखे राजनीतिक मैदान में 'संजीवनी'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में 2027 की चुनावी बिसात अभी पूरी तरह बिछी भी नहीं है कि एक ऐसा मुद्दा आकार लेने लगा है, जो आने वाले दिनों में दोनों प्रमुख दलों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर अगर वह उत्तराखंड पहुंचकर गिरफ्तारी देने का राजनीतिक फैसला लेते हैं, तो यह महज कानूनी कार्रवाई नहीं रहेगी। इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा बड़े होंगे। कांग्रेस के लिए यह घटनाक्रम सूखे राजनीतिक मैदान में संजीवनी साबित हो सकता है, जबकि भाजपा के सामने ऐसा मुद्दा खड़ा हो सकता है, जिसे संभालना आसान नहीं होगा। खासकर तब, जब गिरफ्तारी को कांग्रेस राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर जनता के बीच ले जाने की कोशिश करे।

राहुल गांधी यदि खुद उत्तराखंड पहुंचकर गिरफ्तारी देने का ऐलान करते हैं, तो कांग्रेस के पास इसे बड़े राजनीतिक अभियान में बदलने का अवसर होगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लामबंद करने से लेकर राष्ट्रीय नेताओं की सक्रियता तक, पूरा घटनाक्रम तेजी से प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन सकता है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लंबे समय से सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कानून-व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों के साथ उसे एक बड़ा राजनीतिक चेहरा और भावनात्मक नैरेटिव भी मिल जाएगा। यानी कांग्रेस जिस मुद्दे को अभी प्रदेश की सीमा में लड़ रही है, राहुल गांधी की संभावित गिरफ्तारी उसे राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा सकती है।

भाजपा के सामने मुश्किल यह होगी कि वह इस मामले को कितना कानूनी और कितना राजनीतिक रहने देती है। कार्रवाई होती है तो कांग्रेस इसे राजनीतिक दमन बताएगी और कार्रवाई नहीं होती तो भाजपा पर कानून के सवाल उठ सकते हैं।

◆राहुल गांधी की गिरफ्तारी से मिलेगी कांग्रेस को आक्सीजन
◆उत्तराखंड में भाजपा के सामने आ सकता है सियासी संकट
◆मुद्दा एफआईआर से निकलकर सूबे की सियासत में पहुंचेगा
◆एक बड़ा राजनीतिक चेहरे के साथ मिलेगा भावनात्मक नैरेटिव
◆आरोपी से ज्यादा राजनीतिक प्रतीक बन जाएंगे राहुल गांधी

यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी राजनीतिक पेचीदगी है। भाजपा चाहेगी कि मामला कानून और एफआईआर तक सीमित रहे। कांग्रेस की कोशिश स्वाभाविक रूप से इसे लोकतंत्र, अभिव्यक्ति और राजनीतिक संघर्ष का मुद्दा बनाने की होगी। अगर कांग्रेस अपना नैरेटिव स्थापित करने में सफल होती है तो भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में आना पड़ सकता है।

राहुल गांधी का उत्तराखंड पहुंचना अपने आप में कांग्रेस संगठन के लिए बड़ा राजनीतिक अवसर होगा। प्रदेशभर से कार्यकर्ताओं के जुटने, प्रदर्शन और विरोध की राजनीति शुरू हो सकती है। राष्ट्रीय मीडिया की निगाहें भी उत्तराखंड पर टिकेंगी। कांग्रेस इसे डरेंगे नहीं, लड़ेंगे जैसे राजनीतिक संदेश में बदल सकती है। इससे प्रदेश संगठन में नई ऊर्जा आने की संभावना है। विशेषकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए यह महत्वपूर्ण है। पार्टी को एक ऐसे मुद्दे की जरूरत है, जो संगठन को सड़क पर उतार सके और अलग-अलग गुटों को एक मंच पर ला सके। राहुल गांधी की संभावित गिरफ्तारी ऐसा ही मुद्दा बन सकती है।

कांग्रेस को यह भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ राजनीतिक नारे से चुनाव नहीं जीते जाते। गिरफ्तारी का मुद्दा तभी राजनीतिक लाभ देगा, जब पार्टी इसे उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों से जोड़ सके। अगर पूरा अभियान केवल राहुल गांधी बनाम भाजपा तक सीमित रह गया, तो भाजपा इसे कांग्रेस की व्यक्तिवादी राजनीति बताकर पलटवार कर सकती है। भाजपा का तर्क होगा कि कानून अपना काम करेगा और किसी नेता को राजनीतिक पहचान के आधार पर विशेष छूट नहीं मिल सकती। यहीं से असली राजनीतिक मुकाबला शुरू होगा।

उत्तराखंड में भाजपा लगातार संगठन को मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर

◀◀ शेष पृष्ठ 7 पर

दून वैली मेल

संपादकीय

बदइंतजामी का कहर

उत्तराखंड में आसमान खुलकर बरस रहा है और पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। कहीं सड़क नदी में समा रही है, कहीं मलबा घरों की चौखट तक पहुंच गया है, कहीं पुलों पर खतरा मंडरा रहा है तो कहीं स्कूल और अस्पताल तक असुरक्षित हो गए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग से लेकर गांवों की संपर्क सड़कों तक बारिश ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। हर साल मानसून आता है, बादल बरसते हैं और सरकारें आपदा प्रबंधन के दावे करती हैं। लेकिन सवाल वही है। आखिर हर मानसून में उत्तराखंड इतना बेबस क्यों दिखाई देता है? बारिश प्राकृतिक है, लेकिन बारिश से होने वाली हर तबाही प्राकृतिक नहीं होती। पहाड़ की भौगोलिक संवेदनशीलता किसी से छिपी नहीं है। हिमालय युवा पर्वत है, यहां भूस्खलन और भू-धंसाव का खतरा हमेशा रहेगा। लेकिन जब पहाड़ की क्षमता से अधिक सड़कें काटी जाएं, ढलानों को बिना वैज्ञानिक अध्ययन के छेड़ा जाए, नदियों के किनारों पर निर्माण हो, मलबा सीधे नदी-नालों में डाला जाए और जल निकासी की व्यवस्था कागजों में सीमित रह जाए, तो फिर आपदा को केवल प्रकृति का प्रकोप कहकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। सबसे बड़ा संकट यह है कि उत्तराखंड ने आपदा से सीखने की बजाय आपदा के बाद राहत देने की आदत विकसित कर ली है। सड़क टूटी तो जेसीबी पहुंची, पुल बहा तो वैकल्पिक मार्ग की घोषणा हुई, गांव कट गया तो राशन पहुंचा और भवन क्षतिग्रस्त हुआ तो मुआवजे की बात शुरू हो गई। लेकिन यह व्यवस्था उस सवाल का जवाब नहीं देती कि वही सड़क अगले साल फिर क्यों टूटेगी? वही पहाड़ फिर क्यों दरकेगा? वही नदी फिर क्यों बस्तियों के लिए खतरा बनेगी? हर बार मौत के बाद मुआवजा देना सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मौत रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के विकास माडल पर भी अब गंभीर बहस जरूरी है। विकास का अर्थ केवल चौड़ी सड़क, बड़ी सुरंग, ऊंची इमारत और नए निर्माण नहीं हो सकता। पहाड़ की प्रकृति को समझे बिना किया गया विकास अंतत: विनाश का रास्ता खोल सकता है। सड़क चाहिए, लेकिन ऐसी सड़क चाहिए जो पहाड़ को काटकर नहीं, पहाड़ की प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर बने। सुरंग चाहिए, लेकिन भूगर्भीय अध्ययन और सुरक्षा मानकों के साथ। पर्यटन चाहिए, लेकिन वह स्थानीय पर्यावरण और संसाधनों की क्षमता के अनुरूप हो। विडंबना यह है कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन पर चर्चाएं अक्सर तब तेज होती हैं जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। कुछ दिन तक बैठकें होती हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, हेल्पलाइन जारी होती है और फिर मौसम साफ होते ही सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है। जबकि पहाड़ को केवल मानसून के दिनों में नहीं, पूरे साल बचाने की जरूरत है। सरकार को अब रेस्क्यू से आगे बढ़कर रिस्क प्रिवेंशन की नीति अपनानी होगी। संवेदनशील गांवों की वैज्ञानिक मैपिंग हो। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान हो। पुराने पुलों और सड़कों का स्ट्रक्चरल ऑडिट हो। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी भवनों की सुरक्षा जांच हो। नदी-नालों के प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र में अतिक्रमण पर कठोर कार्रवाई हो। निर्माण की अनुमति केवल कागजी नक्शों के आधार पर नहीं, बल्कि भूगर्भीय और पर्यावरणीय जोखिम के आकलन के आधार पर दी जाए और सबसे जरूरी है आपदा के नाम पर खर्च होने वाले पैसे का सामाजिक आडिट हो। उत्तराखंड की जनता को हर साल एक ही तस्वीर देखने को मिलती है। बारिश शुरू, सड़क बंद, बारिश तेज, गांव अलग-थलग, नदी बढ़ी, प्रशासन अलर्ट, सड़क टूटी, मरम्मत का आदेश। आखिर यह चक्र कब टूटेगा? यह सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, पूरे राजनीतिक तंत्र से है। सत्ता चाहे किसी भी दल की हो, पहाड़ की पीड़ा किसी पार्टी की नहीं होती। आपदा के समय आरोप-प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है साझा रणनीति। विपक्ष को भी केवल बयानबाजी तक सीमित रहने के बजाय सरकार से ठोस जवाब मांगना होगा कि कितने संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित हुए, कितने सुरक्षित किए गए और पिछले वर्षों की आपदाओं से क्या सीखा गया? उत्तराखंड को राहत की राजनीति नहीं, सुरक्षा की राजनीति चाहिए। यह समय भीड़ बढ़ाने वाले पर्यटन माडल पर पुनर्विचार का है। यह समय पहाड़ की वहन क्षमता तय करने का है। यह समय नदियों को केवल बिजली उत्पादन और निर्माण की जमीन मानने की मानसिकता बदलने का है। यह समय यह स्वीकार करने का है कि हिमालय कोई खाली जमीन नहीं, बल्कि एक जीवित और अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। आज अगर पहाड़ की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले वर्षों में बारिश का हर मौसम और भयावह हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है। कम समय में अत्यधिक बारिश, अचानक बाढ़ और असामान्य मौसम की घटनाएं नीति-निर्माताओं के सामने नई चुनौती हैं। ऐसे में पुराने अनुभवों और पुराने ढर्रे से उत्तराखंड की सुरक्षा नहीं हो सकती। उत्तराखंड को सिर्फ आपदा से बचाना नहीं है, उसे ऐसी विकास नीति देनी है जिसमें आपदा का खतरा ही कम हो। बारिश पहाड़ की दुश्मन नहीं है। बारिश तो इसी हिमालय की जीवनधारा है। असली खतरा तब पैदा होता है जब इंसान प्रकृति की सीमा भूल जाता है। इसलिए इस मानसून की सबसे बड़ी सीख यही होनी चाहिएकृपहाड़ को जीतने की कोशिश बंद कीजिए, पहाड़ के साथ जीना सीखिए। क्योंकि अगर हमने अब भी नहीं सीखा, तो अगली बारिश सिर्फ पानी लेकर नहीं आएगी। वह हमारी विकास नीतियों का हिसाब भी मांग सकती है।

सत्ता, धर्म और विचारधारा की लड़ाई का 'नया मोर्चा'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से जुड़े शुद्धिकरण प्रकरण ने उत्तराखंड की सियासत को गरमा दिया है। मंच पर गंगाजल छिड़कने और शुद्धिकरण हवन को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। मामला अब महज एक राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके बहाने दोनों दल एक-दूसरे की विचारधारा, राजनीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा जहां इसे कांग्रेस की सत्ता की बेचैनी और तुष्टिकरण की राजनीति से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस इसे भाजपा की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति का उदाहरण बता रही है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार राजनीतिक रंग देकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाना चाहती है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को जनता के बीच अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का अहसास हो चुका है, इसलिए वह ऐसे मुद्दों के सहारे राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेताओं ने इसे कांग्रेस की सत्ता की भूख से जोड़ते हुए कहा कि जनता अब इस तरह की राजनीति को स्वीकार करने वाली नहीं है।

भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा धार्मिक आस्था का सम्मान किया है और किसी भी धार्मिक प्रतीक को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश उचित नहीं है। पार्टी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े विषयों पर राजनीति करने के बजाय उसे अपने शासन और नीतियों का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। भाजपा के निशाने पर कांग्रेस के साथ-साथ राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व भी है। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस एक तरफ संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बात करती है, दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवादों को राजनीतिक संघर्ष का हथियार बनाती है।

कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा खुद इस मामले को लगातार राजनीतिक मुद्दा बना रही है और अब कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा को महंगाई, बेरोजगारी,

◆प्रदेश से खिसकती जमीन और सत्ता की छटपटाहट
◆गंगाजल व हवन के बहाने राजनीतिक हिसाब-किताब
◆मुद्दों की सियासत पर भारी पड़ा शुद्धिकरण का दांव
◆देवभूमि में नीयत व विचारधारा का सीधा मुकाबला

रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्तराखंड के विकास जैसे मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन वह धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवादों के जरिए राजनीतिक ध्रुवीकरण का माहौल तैयार करना चाहती है।

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को धार्मिक भावनाओं के नाम पर दूसरे दल को कठघरे में खड़ा करने का अधिकार नहीं है। पार्टी का कहना है कि भाजपा को इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी तय करने के बजाय इसे राजनीतिक प्रचार का हथियार बनाने से बचना चाहिए। शुद्धिकरण प्रकरण की राजनीतिक गूंज उत्तराखंड से बाहर भी सुनाई दे रही है। कांग्रेस और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की बयानबाजी के बाद यह विवाद अब राज्य की राजनीति में एक बड़े प्रतीकात्मक मुद्दे का रूप लेता दिखाई दे रहा है। एक तरफ भाजपा इसे कांग्रेस की कथित सत्ता की हताशा बता रही है, दूसरी ओर कांग्रेस इसे भाजपा की धर्म आधारित राजनीति के रूप में पेश कर रही है। दोनों दलों के लिए यह विवाद आगामी राजनीतिक संघर्ष की जमीन तैयार करने का अवसर भी बन गया है।

इस विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या धर्म और आस्था से जुड़े प्रतीकों को राजनीतिक संघर्ष का हथियार बनाया जाना चाहिए? गंगाजल और शुद्धिकरण जैसे धार्मिक प्रतीकों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब आरोप-प्रत्यारोप के ऐसे दौर में पहुंच गया है, जहां दोनों दल एक-दूसरे की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा इसे कांग्रेस की सत्ता पाने की बेचैनी बता रही है तो कांग्रेस भाजपा पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है। दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में धर्म और आस्था हमेशा संवेदनशील विषय रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों के लिए चुनौती यह है कि राजनीतिक लाभ के लिए उठाए गए कदम कहीं सामाजिक विभाजन को और गहरा न कर देंउत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज होने के साथ ही इस विवाद का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। भाजपा सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में 'शुद्धिकरण' विवाद दोनों दलों के लिए एक-दूसरे पर हमला बोलने का नया हथियार बन गया है। आने वाले दिनों में यह विवाद कितना लंबा खिंचता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना तय है कि हल्द्वानी का शुद्धिकरण अब केवल एक धार्मिक प्रतीक का विवाद नहीं रहा यह उत्तराखंड की सियासत में सत्ता, धर्म और विचारधारा की लड़ाई का नया मोर्चा बन चुका है।

रोपवे परियोजनाओं के लिए रोपवे रेग्यूलेशन और रूल्स शीघ्र हों जारी: बर्द्धन

संवाददाता

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने ब्रिडकुल को प्रदेश में रोपवे परियोजनाओं के प्रभावी संचालन एवं नियमन के लिए रोपवे रेग्यूलेशन और रूल्स शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।

आज यहां मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश में संचालित एवं प्रस्तावित विभिन्न रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने ब्रिडकुल को प्रदेश में रोपवे परियोजनाओं के प्रभावी संचालन एवं नियमन के लिए रोपवे रेग्यूलेषन और रूल्स शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं में तेजी लाते हुए लंबित प्रक्रियाओं, भूमि संबंधी प्रकरणों एवं आपसी समन्वय से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे कनेक्टिविटी प्रदेश की पर्यटन एवं यातायात व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए सभी परियोजनाओं में समयबद्धता, गुणवत्ता एवं आपसी समन्वय पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि रोपवे परियोजनाओं में पार्किंग डेवलपमेंट को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके। मुख्य सचिव ने केदारनाथधाम एवं हेमकुंड साहिब रोपवे की प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित एजेंसियों को परियोजना की आगामी कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला प्रशासन एवं कार्यदायी संस्था के बीच बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश भी दिए गए। नैनीताल क्षेत्र की रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा के दौरानउन्होंने रानीबा-ज्योलीकोट हनुमानगढ़ी-कैंचीधाम तथा रानीबाग-भीमताल-भवाली रोपवे परियोजनाओं में एन एच एल एम एल एवं यूकेएमआरसी को आपसी तालमेल से इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यूकेएमआरसी के प्रोजेक्ट के फाइनल अप्रूवल की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने के साथ ही फाईनल डीपीआर तथा डीएफसी की प्रक्रिया को भी शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देष दिए। मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग द्वारा निर्माण की जा रही परियोजनाओं जोशीमठ-औली-गोरसों, रैथल-बारसू तथा पुरकुल रोपवे परियोजनाओं की भी समीक्षा की।

उन्होंने इन परियोजनाओं की नियमित एवं प्रभावी समीक्षा करते हुए आवश्यक प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यमुनोत्री-जानकी चट्टी, हनुमानचट्टी-पूर्णागिरि एवं तपोवन-कुंजपुरा रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने इनसे सम्बन्धित लम्बित कार्यों को शीघ्र पूरा करने को कहा गया।

बीरोंखाल के गांवों में वायरल का प्रकोप, रोज पहुंच रहे 80 मरीज

कोटद्वार(आरएनएस)। बीरोंखाल ब्लॉक में लगातार हो रही बारिश के बीच वायरल का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बीरोंखाल और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में बड़ी संख्या में ग्रामीण बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। सीएचसी में प्रतिदिन करीब 80 मरीज वायरल से पीड़ित होकर उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में पिछले करीब एक माह से वायरल का सिलसिला जारी है। ग्रामीण विमला बिष्ट ने बताया कि आसपास के कई घरों में लोग पिछले एक माह से बुखार से पीड़ित हैं। सीएचसी बीरोंखाल के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. शैलेंद्र रावत ने बताया कि इन दिनों अस्पताल में रोज करीब 80 मरीज वायरल की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।

क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य उपकेंद्रों में भी कमोबेश यही स्थिति है। लगातार बारिश, अचानक तेज धूप में निकलने, बारिश में भीगने और मौसम में बदलाव के कारण वायरल के मामले बढ़ रहे हैं।उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने, मास्क का प्रयोग करने, ठंडे पदार्थों से परहेज करने और बारिश में भीगने से बचने की अपील की। सामान्य वायरल उचित देखभाल और उपचार से करीब एक सप्ताह में ठीक हो जाता है। तेज बुखार या गंभीर लक्षण होने पर चिकित्सक से जांच कराना जरूरी है। डॉ. रावत ने बताया कि अस्पताल में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम में ऊधम सिंह नगर प्रदेश में तीसरे स्थान पर

रुद्रपुर(आरएनएस)। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में ऊधम सिंह नगर ने प्रदेश में तृतीय स्थान हासिल कर महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति, योजनाओं की निगरानी और जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में बेहतर प्रदर्शन के लिए जिले को सम्मानित किया गया।

देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष रामपाल सिंह, ज्योति प्रसाद गिरोला और निदेशक सुशील कुमार ने ऊधम सिंह नगर को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न प्रदान किया। जिले की इस उपलब्धि का श्रेय जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों को दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने में जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया। समिति के उपाध्यक्ष रामपाल सिंह ने जिलाधिकारी, सीडीओ समेत अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने आगामी वर्ष ऊधम सिंह नगर के प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने की उम्मीद जताई।

जल जीवन मिशन का भुगतान लटका, ठेकेदारों ने किया प्रदर्शन

बागेश्वर(आरएनएस)। जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्यों का भुगतान लंबे समय से लंबित होने से नाराज ठेकेदारों ने जिला कार्यालय में प्रदर्शन किया। सिविल कॉन्ट्रेक्टर्स सोसायटी के अध्यक्ष गंगा सिंह कोरंगा के नेतृत्व में ठेकेदारों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की।

ठेकेदारों ने बताया कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत जल निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग कपकोट की ओर से विभिन्न पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया गया। कई योजनाओं का निर्माण, मूल्यांकन और हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन वर्ष 2023-24 से भुगतान लंबित है।ठेकेदारों का कहना है कि भुगतान नहीं होने से मजदूरों की मजदूरी और निर्माण सामग्री का भुगतान करना मुश्किल हो गया है। इससे ठेकेदार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और कई निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। ठेकेदारों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और पेयजल मंत्री को ज्ञापन भेजकर एक सप्ताह के भीतर लंबित भुगतान कराने की मांग की। चेतावनी दी कि समय पर भुगतान नहीं होने पर वे आमरण अनशन, आंदोलन और न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होंगे। इस दौरान अमर सिंह बिष्ट, राजेंद्र नगरकोटी, हरीश चंद्र सिंह शाही, हरीश चंद्र चंदोला, पान सिंह, प्रताप सिंह और केदार सिंह समेत अन्य ठेकेदार मौजूद रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

पवित्र मैदान पर 'गंदी सियासत'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। हल्द्वानी का रामलीला मैदान इन दिनों राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस जहां भाजपा और हिंदू संगठनों पर हमलावर है, वहीं भाजपा ने अब इस विवाद को एक अलग कोण से उठाना शुरू कर दिया है। भाजपा का कहना है कि जिस रामलीला मैदान का स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में महत्व रहा है, वहां हुई घटना को केवल जातिगत चश्मे से देखना उत्तराखंड की सनातन परंपरा और स्थानीय आस्था के साथ अन्याय है।

भाजपा का तर्क है कि विवाद में शामिल प्रत्येक पक्ष की भूमिका और उसके बयान की जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए पूरे घटनाक्रम को दलित बनाम सवर्ण या दलित बनाम सनातन की बहस में बदलना समाज को बांटने की कोशिश है। हल्द्वानी का रामलीला मैदान लंबे समय से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों का प्रमुख स्थल रहा है। रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों के कारण इस मैदान की पहचान स्थानीय जनजीवन में केवल एक सार्वजनिक मैदान के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े स्थान के तौर पर भी बनी है। यही वजह है कि भाजपा इस पहलू को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला रही है।

भाजपा नेताओं का सवाल है कि यदि किसी धार्मिक-सांस्कृतिक स्थल पर कोई विवाद पैदा होता है तो उसकी संवेदनशीलता को समझना जरूरी है। उसे तत्काल जातीय संघर्ष की भाषा में बदल देना क्या उचित है? भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस इस विवाद को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

पार्टी नेताओं के अनुसार कांग्रेस के पास भाजपा को घेरने के लिए सामाजिक न्याय और दलित सम्मान का मुद्दा है, लेकिन इस बहस में सनातन परंपराओं और स्थानीय धार्मिक भावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। भाजपा का कहना है कि दलित सम्मान और सनातन सम्मान को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करना ही असली राजनीतिक साजिश है। पार्टी के मुताबिक उत्तराखंड की सामाजिक संरचना को इस तरह की विभाजनकारी राजनीति से बचाना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।

कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण क्यों किया गया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भाजपा इस सवाल पर सीधे बचाव करने के बजाय अब बहस का फोकस बदलने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि किसी भी घटना पर कानून अपना काम करे, लेकिन धार्मिक स्थल और धार्मिक परंपराओं को लेकर संवेदनशीलता भी जरूरी है। यहीं से भाजपा का राजनीतिक पलटवार शुरू होता है। भाजपा नेताओं का सवाल है कि क्या किसी धार्मिक परंपरा को लेकर उठे विवाद को सीधे जातिवाद का नाम देकर खत्म कर देना उचित होगा?

◆रामलीला मैदान विवाद में बीजेपी ने बदला पैंतरा, कांग्रेस को घेरा
◆खड़गे विवाद पर बीजेपी की दो टूक परंपरा से खिलवाड़ मंजूर नहीं
◆रामलीला मैदान का धार्मिक महत्व जानते हुए भी हो रही है सियासत
◆भाजपा का सवाल धार्मिक आस्था के स्थल को राजनीतिक अखाड़ा

कांग्रेस के लिए भाजपा का यह नैरेटिव चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को दलित सम्मान और सामाजिक बराबरी का सवाल बनाना चाहती है। भाजपा इसे सनातन परंपरा, धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव से जोड़ रही है। इस तरह दोनों दल एक ही घटना से दो बिल्कुल अलग राजनीतिक संदेश निकाल रहे हैं। कांग्रेस का संदेश सामाजिक बराबरी से समझौता नहीं। भाजपा का संदेश धार्मिक आस्था को राजनीतिक हथियार मत बनाइए। यानी विवाद अब केवल हल्द्वानी तक सीमित नहीं रह गया है। यह उत्तराखंड में उस बड़े राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन रहा है जिसमें सामाजिक न्याय बनाम सांस्कृतिक अस्मिता के अलग-अलग नैरेटिव सामने आ रहे हैं।

भाजपा कांग्रेस से यह भी पूछ रही है कि क्या हर राजनीतिक विवाद में जाति को केंद्र में रखना जरूरी है? पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड का समाज लंबे समय से विभिन्न जातियों, समुदायों और परंपराओं के सह-अस्तित्व का उदाहरण रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों को ऐसे मुद्दों पर और अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि कथित शुद्धिकरण जैसी घटना को सामान्य धार्मिक परंपरा बताकर टाला नहीं जा सकता। उसका कहना है कि सामाजिक बराबरी और सम्मान के सवाल को दबाया नहीं जा सकता। यही टकराव अब पूरे विवाद को और तीखा बना रहा है।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक तैयारियां तेज होने के साथ इस विवाद का चुनावी महत्व भी बढ़ गया है। भाजपा जहां अपने हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नैरेटिव को मजबूती देने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस सामाजिक न्याय, संविधान और बराबरी को अपने अभियान का प्रमुख आधार बना सकती है। हल्द्वानी का रामलीला मैदान इसलिए अब केवल विवाद का स्थल नहीं, बल्कि दो राजनीतिक विचारधाराओं की टकराहट का प्रतीक बनता जा रहा है।

भाजपा का सवाल है कि सनातन परंपरा और दलित सम्मान को आमने-सामने खड़ा करके आखिर किसका राजनीतिक फायदा होगा? कांग्रेस का सवाल है कि धार्मिक आस्था के नाम पर सामाजिक भेदभाव को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यही दो सवाल आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सियासत का तापमान तय करेंगे। रामलीला मैदान की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान अपनी जगह है और सामाजिक समानता का संवैधानिक सिद्धांत अपनी जगह। राजनीतिक दलों के सामने चुनौती यही है कि आस्था और अधिकार की इस बहस को समाज को बांटने का हथियार बनने से कैसे रोका जाए।

रोडवेज परिसर में जलभराव से यात्री और कारोबारी परेशान

हल्द्वानी(आरएनएस)। रोडवेज बस स्टेशन परिसर जलभराव यात्रियों और स्थानीय कारोबारियों को बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। परिसर में जलनिकासी की उचित व्यवस्था न होने से जल निकासी अवरुद्ध हो गई है। इसका सीधा असर दैनिक यात्रियों पर पड़ रहा है, जिन्हें जलमग्न परिसर के बीच बसों में चढ़ने-उतरने के दौरान भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पाइपलाइन का इनलेट लेवल सड़क और बस स्टैंड परिसर के जमीनी स्तर से काफी ऊपर स्थापित कर दिया गया है। इस कारण डिपो परिसर में पानी जमा हो रहा है। प्रशासनिक अनदेखी के चलते स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि परिसर के दुकानदारों को अपने स्तर पर ट्यूबवेल पंप लगाकर जल निकासी करनी पड़ रही है। हल्द्वानी डिपो के एआरएम संजय पांडे सहित स्थानीय दुकानदारों और यात्रियों ने नगर निगम प्रशासन से तकनीकी मूल्यांकन कर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।

सामान्य स्थानांतरण शुरू करने की मांग, दो साल से लंबित नीति पर उठाए सवाल

अल्मोड़ा(आरएनएस)। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने शिक्षा विभाग से लंबित सुगम-दुर्गम नीति पर शीघ्र निर्णय लेने और सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि दो वर्षों से नीति लंबित रहने के कारण हजारों शिक्षक और कार्मिक प्रभावित हो रहे हैं तथा उनमें असंतोष बढ़ रहा है। संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार जोशी और जिला सचिव धीरेन्द्र कुमार पाठक ने जारी बयान में कहा कि वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया में केवल विभिन्न श्रेणियों (कैटेगरी) के आधार पर प्रदेशभर में दो हजार से अधिक स्थानांतरण किए गए हैं, जबकि सामान्य अनुरोध के आधार पर होने वाले स्थानांतरण न्यायालय में लंबित सुगम-दुर्गम नीति का हवाला देकर रोक दिए गए हैं। उनका कहना है कि न्यायालय ने अन्य आधारों पर स्थानांतरण करने से विभाग को नहीं रोका है, इसलिए सामान्य स्थानांतरण भी किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को अपनी स्थानांतरण नीति की समीक्षा कर स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। लगातार दूसरे वर्ष सामान्य स्थानांतरण प्रभावित होना कर्मचारियों के हितों के विपरीत है। संगठन का कहना है कि वर्ष 2027 की स्थानांतरण प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से लागू की जाए ताकि सभी पात्र कार्मिकों और शिक्षकों को समान अवसर मिल सके। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानांतरण में 17(1)(ख) श्रेणी के प्रकरणों को प्राथमिकता नहीं दी गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इस पर विभाग से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की गई है। संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिगम्बर फुलोरिया, उपाध्यक्ष महेश आर्य, संयुक्त मंत्री डी.के. जोशी, राजेंद्र सिंह लटवाल, कार्यालय सचिव गणेश भंडारी, संगठन मंत्री दीपक तिवारी, तारा सिंह बिष्ट, भगवत सिंह सतवाल, कोषाध्यक्ष संजय जोशी और ऑडिटर दीपशिखा मेलकन्या सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्थानांतरण नीति को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू करने की मांग की है।

रोज माउथवॉश करते हैं तो पहले जान लें ये जरूरी बातें, वर्ना फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

सुबह उठते ही ब्रश करना और फिर मुंह की ताजगी के लिए माउथवॉश का इस्तेमाल करना अब कई लोगों की रोज की आदत बन चुका है। कुछ लोग इसे सांसों की बदबू दूर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ को लगता है कि माउथवॉश करने से दांत और मसूड़े ज्यादा साफ रहेंगे। हालांकि माउथवॉश मुंह की सफाई में मदद जरूर करता है, मगर यह ब्रश और दांतों के बीच की सफाई नहीं कर सकता। साथ ही, हर दिन इस्तेमाल करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि आप किस तरह का माउथवॉश इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका सही तरीका क्या है। माउथवॉश से कुल्ला करने के बाद मुंह ताजगी भरा जरूर लगता है, लेकिन इससे दांतों पर जमी गंदगी पूरी तरह नहीं निकलती। ब्रश दांतों की सतह पर जमा गंदगी और प्लाक को हटाने में मदद करता है। वहीं दांतों के बीच फंसे खाने को साफ करने के लिए के लिए फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश की जरूरत पड़ती है। इसलिए माउथवॉश को ब्रश का विकल्प मानना गलत है। इसे जरूरत के मुताबिक रोज की ओरल हाइजीन रूटीन में शामिल किया जा सकता है। बाजार में कई तरह के माउथवॉश मिलते हैं। किसी का इस्तेमाल बदबू के लिए किया जाता है, तो किसी को मसूड़ों या दूसरी दांतों की परेशानी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसलिए सिर्फ अच्छा स्वाद या बड़ी कंपनी देखकर माउथवॉश खरीदना सही नहीं है। अगर आपको दांत या मसूड़ों से जुड़ी कोई परेशानी है तो डेंटिस्ट से पूछकर माउथवॉश लेना बेहतर रहेगा। कुछ माउथवॉश इस्तेमाल करने पर मुंह में तेज जलन होती है। कई लोगों को लगता है कि जलन ज्यादा है तो माउथवॉश ज्यादा असरदार होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। जलन कुछ खास चीजों की वजह से हो सकती है, जैसे अल्कोहल या उसमें डाला गया फ्लेवर। अगर हर बार इस्तेमाल के बाद ज्यादा जलन या परेशानी हो रही है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। माउथवॉश खरीदने से पहले उसकी बोतल पर दी गई जानकारी जरूर पढ़ें। उसमें कौन-कौन सी चीजें डाली गई हैं, यह देखना जरूरी है। खासकर अगर आपका मुंह जल्दी सूखता है या किसी चीज से जलन होती है तो ऐसा प्रोडक्ट चुनने से बचें, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। हर व्यक्ति के लिए एक ही माउथवॉश सही हो, यह जरूरी नहीं है। अगर माउथवॉश करने के बाद सांसों की बदबू वापस बनी रहती है तो इसकी वजह कुछ और हो सकती है। दांतों और मसूड़ों की बीमारी भी इसकी वजह बन सकती है। ऐसे में बार-बार माउथवॉश करने के बजाय डेंटिस्ट से जांच कराना ज्यादा बेहतर रहेगा।

नियमित तौर पर वालीबॉल खेलने से मिल सकते हैं ये 5 प्रमुख फायदे

वालीबॉल एक मजेदार और रोमांचक खेल है, जो न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह खेल टीम वर्क, ध्यान और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है। वालीबॉल खेलने से शरीर के विभिन्न हिस्सों की एक्सरसाइज होती है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आइए जानते हैं कि नियमित रूप से वालीबॉल खेलने से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।

शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा: वालीबॉल खेलने से शरीर की फिटनेस में सुधार होता है। यह खेल दौड़ने, कूदने और तेजी से हरकत करने की जरूरत होती है, जिससे दिल और फेफड़ों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके अलावा यह खेल मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर को लचीला बनाता है। नियमित रूप से वालीबॉल खेलने से शरीर की सहनशक्ति भी बढ़ती है, जिससे आप अन्य खेल गतिविधियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

तनाव को कम करने में है मददगार: वालीबॉल खेलने से मानसिक तनाव कम होता है। जब आप किसी टीम का हिस्सा होते हैं और मिलकर खेलते हैं तो आपका ध्यान अपनी चिंताओं से हट जाता है। यह खेल आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको खुश रखता है। इसके अलावा वालीबॉल खेलने से ऐसे रसायन निकलते हैं, जो आपको खुश और तरोताजा महसूस कराते हैं। नियमित रूप से वालीबॉल खेलने से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।

सामाजिक संबंध मजबूत करने में है सहायक: वालीबॉल एक टीम गेम है, जो सामाजिक संबंध बनाने का अच्छा मौका देता है। जब आप किसी टीम का हिस्सा होते हैं तो आप नए दोस्तों से मिलते हैं और साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। इससे आपकी सामाजिक कौशल भी विकसित होती हैं। इसके अलावा यह खेल सहयोग और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है, जो आपके व्यक्तिगत संबंधों को भी मजबूत करता है। नियमित रूप से वालीबॉल खेलने से आप एक समुदाय का हिस्सा बनते हैं।

संतुलन और तालमेल में सुधार: वालीबॉल खेलने से शरीर का संतुलन और तालमेल में सुधार होता है। गेंद को सही तरीके से हिट करना, कूदना और जमीन पर उतरना इन सभी गतिविधियों से आपका संतुलन बेहतर होता है। इसके अलावा यह खेल हाथ-आंख के संतुलन को भी बढ़ावा देता है। नियमित रूप से वालीबॉल खेलने से आप अपने शरीर के नियंत्रण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं।

आत्मविश्वास बढ़ाने में है कारगर: वालीबॉल खेलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप किसी टीम का हिस्सा बनकर जीत हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आपकी व्यक्तिगत पहचान भी मजबूत होती है और आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं।

इस प्रकार वालीबॉल न केवल एक खेल है बल्कि एक जीवनशैली है, जो हमें स्वस्थ रखने के साथ-साथ मनोबल भी बढ़ाती है। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसके लाभ उठाएं।

अपमान पर पर्दा, सवाल उठाने पर केस

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर ने उत्तराखंड की सियासत को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस ने अब इस पूरे विवाद को महज उत्तराखंड का स्थानीय मामला मानने से इनकार करते हुए इसे दलित सम्मान, सामाजिक बराबरी और संविधान की लड़ाई से जोड़ दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस का आक्रोश और बढ़ गया है। पार्टी का आरोप है कि खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित शुद्धिकरण पर कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी की आवाज को एफआईआर के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए आंदोलन को देशव्यापी स्वर देने का फैसला किया है।

कांग्रेस की रणनीति अब साफ दिखाई दे रही है। पार्टी इस विवाद को केवल मंच शुद्धिकरण तक सीमित नहीं रखना चाहती। उसका निशाना अब सीधे भाजपा की राजनीतिक और वैचारिक राजनीति पर है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कथित शुद्धिकरण में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। कांग्रेस का कहना है कि जब इस मांग के बाद राहुल गांधी पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तो इससे सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या विपक्ष के नेता को सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है? कांग्रेस नेताओं ने इसी सवाल को लेकर विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रदर्शन हुआ तो झारखंड के धनबाद तक इसका असर दिखाई दिया। कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एफआईआर और कथित शुद्धिकरण के खिलाफ आवाज उठाई।

राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, जिसके जरिए वह भाजपा को सीधे सामाजिक न्याय और संविधान के सवाल पर घेरना चाहती है। खड़गे स्वयं दलित समुदाय से आने वाले राष्ट्रीय नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस का तर्क है कि उनके कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण की घटना को सामान्य

◆कांग्रेस द्वारा इसे महज उत्तराखंड का मामला न मानकर राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही, विवाद को राष्ट्रीय पहचान देने और कांग्रेस के आगामी रणनीतिक का बड़ा प्लान

राजनीतिक विवाद मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। पार्टी इसे सामाजिक भेदभाव के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है। राहुल गांधी ने भी इसे इसी बड़े विमर्श से जोड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर समेत कई नेताओं ने घटना की आलोचना की है। अब पार्टी की कोशिश इस सवाल को गांव, शहर और प्रदेश स्तर तक ले जाने की है। अगर संविधान समानता की गारंटी देता है तो जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के सम्मान को लेकर अलग व्यवहार क्यों?

इस विवाद का सबसे सीधा असर उत्तराखंड की राजनीति पर पड़ना तय है। कांग्रेस पहले ही हल्द्वानी की घटना को लेकर आक्रामक है और देहरादून में सचिवालय घेराव का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस के लिए यह आंदोलन केवल भाजपा विरोध का माध्यम नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक नैरेटिव को धार देने का अवसर भी बन गया है। भाजपा जहां कांग्रेस पर मामले को जातिगत राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस इसे भाजपा की कथित सामाजिक सोच का आईना बता रही है। यानी आने वाले दिनों में यह विवाद कानूनी लड़ाई से ज्यादा राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई बन सकता है।

कांग्रेस का हमला अब दो सवालों पर केंद्रित हैकृपहला, खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित शुद्धिकरण पर क्या कार्रवाई हुई? दूसरा, राहुल गांधी के बयान पर एफआईआर क्यों? भाजपा के लिए चुनौती यह है कि वह इस विवाद को केवल राहुल गांधी के बयान तक सीमित रखकर कांग्रेस के राजनीतिक हमले को रोक पाएगी या नहीं। क्योंकि कांग्रेस अब इसे राहुल बनाम भाजपा का विवाद नहीं रहने देना चाहती। वह इसे सामाजिक सम्मान बनाम भेदभाव के सवाल में बदलने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। पार्टी ने देशभर में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और एफआईआर को ही आंदोलन का राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी है। कांग्रेस का कहना है कि उसके नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है तो कथित शुद्धिकरण के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी हल्द्वानी का विवाद अब उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। एक तरफ भाजपा इसे कांग्रेस की राजनीतिक अवसरवादिता बता रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे संविधान और सामाजिक सम्मान की लड़ाई बना रही है। आने वाले दिनों में असली मुकाबला अदालत या थाने से ज्यादा जनता की अदालत में नैरेटिव तय करने का होगा और यही इस पूरे विवाद को 2027 की उत्तराखंड विधानसभा चुनावी राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण बना देता है।

शब्द सामर्थ्य -055

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. भारत के वर्तमान वित्तमंत्री 6. हित, उपकार 7. असमान, पूर्वोत्तर का एक राज्य 8. किसी वस्तु व्यक्ति आदि के पहचान सूचक संबोधन का शब्द, संज्ञा 10. शवस्थल पर बनाया गया मकान, योग का अंतिम अंग, तपस्या 13. इंकार करना, ना कहना 14. पिता, क्लर्क, सम्मानीय व्यक्ति 15. आय पर लगने वाला टैक्स, इंकमटैक्स 16. प्रतिद्वंद्वी, प्रेमिका का दूसरा प्रेमी 17. परंपरा, रीति, रिवाज 20. रुप से युक्त, चिह्न, लक्षण, नाटक, एक साहित्यिक अलंकार 23. लोग, प्रजा 25. नामी, नामवर, प्रसिद्ध 27. संसार का स्वामी, बादशाह, सम्राट, ईश्वर 28. फैलाना, खिंचाव पैदा करना।

ऊपर से नीचे

1. मारना, प्रहार करना, आघात करना 2. मिथ्याअभिमान, आडंबर 3. विपत्ति, आफत 4. मालदार, धनवान, अमीर 5. ज्ञान प्राप्त करना, अनुमान लगाना, कल्पना करना 7. हक 9. विवश, लाचार 11. मानकंद, नापने का पैमाना 12. अपमानित और तिरस्कृत 17. संतान उत्पन्न करने की क्रिया, जन्म देने की क्रिया 18. लंबे कपड़े का गट्ठा, पशुओं को रखने की जगह 19. जलयान, वायुयान, जलपोत 21. आश्रय, सहारा 22. थोड़ा, जरा, तनिक 24. जुर्म, गुनाह 26. बाघ की तरह का धारीदार हिंसक एवं विशाल पशु।

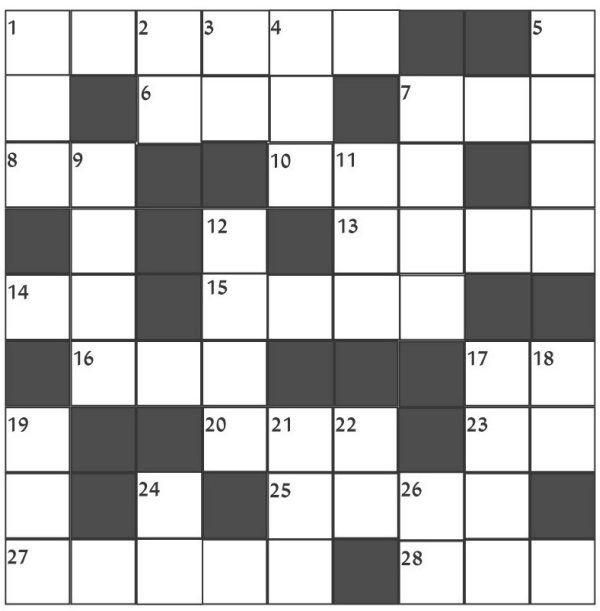

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 54 का हल

भू	कं	प	■	फा	य	दा	■	स
प	■	ल	ला	ट	■	य	ती	म
ति	ल	क	■	क	न	क	■	झ
■	क्ष्म	■	■	■	रे	■	■	■
ग	ण	क	■	सं	श	य	■	सौ
ह	■	या	च	क	■	म	न्न	त
रा	क्ष	स	■	र	क्ष	क	■	न
■	त्रि	■	■	■	मि	■	■	■
शा	य	री	■	का	त	र	■	गो

दृश्यम: द कन्क्लूजन से स्टार कास्ट के फर्स्ट लुक आउट!

अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम- द कन्क्लूजन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी. इससे पहले फिल्म को लेकर दर्शकों की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है. हाल ही में दृश्यम- द कन्क्लूजन का एलान हुआ और फिल्म के किरदारों के आधे चेहरों के साथ उनके नाम भी सामने आए. अब मेकर्स एक-एक कर फिल्म की मुख्य स्टारकास्ट के फर्स्ट लुक जारी कर रहे हैं. साथ ही उनके फर्स्ट लुक के साथ कुछ लाइनें भी छोड़ रहे हैं, जो फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाने का काम कर रहे हैं. फिल्म का मुख्य किरदार विजय सलगांवकर है. इस रोल को अजय देगवन बखूबी निभा रहे हैं. अब फिल्म की तीसरी आखिरी किस्त में उनका काम किस ऊंचाईयों तक पहुंचता है, यह देखना बाकी है. मेकर्स ने अजय का फर्स्ट लुक जारी कर लिखा है, सही या गलत...जो भी हो, मैं अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं.

पिछले दोनों पार्ट में तब्बू ने रोल से दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया है. उनके किरदार का नाम मीरा देशमुख है, जो एक बड़ी पुलिस अधिकारी हैं. फिल्म की तीसरी किस्त से आए उनके फर्स्ट लुक में वह काफी सीरियस लुक में दिख रही हैं. तब्बू का फर्स्ट लुक जारी कर मेकर्स लिखते हैं, इस चौथी फैल को पूरे सिस्टम ने अंडरएस्टिमेट किया था. अब इंसाफ नहीं, मां का बदला होगा.

फिल्म की मुख्य हीरोइन और विजय सलगांवकर की पत्नी के रोल में श्रेया सरन ने भी कुछ कम कमाल नहीं किया है. श्रेया ने फिल्म में अपने रोल नंदिनी सलगांवकर के साथ पूरा न्याय किया है. फिल्म से आए उनके फर्स्ट लुक में वह काफी सहमी हुई दिख रही हैं. श्रेया का फर्स्ट लुक जारी कर मेकर्स लिखते हैं, इतने सालों से नॉर्मल क्या होता है हम भूल ही गए हैं. खतरा अभी भी टला नहीं. रजत कपूर एक बार फिर फिल्म में महेश देशमुख के रोल नजर आएंगे. वह मीरा देशमुख (तब्बू) के पति हैं. फिल्म में उनका रोल बहुत पेचीदा है. उनका किरदार सच के रास्ते पर चलने वाला है, भले ही इसमें अपनों का ही नुकसान क्यों ना हो. इसलिए उनके फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा जाता है, वक्त सच का दृश्य दिखा ही देता है.

दृश्यम- द कन्क्लूजन का मजा अब और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें जयदीप अहलावत जैसे बेहतरीन एक्टर की एंट्री हो चुकी है. फिल्म में उनका रोल एसपी क्राइम ब्रांच रणवीर सिंह तोमर का होगा. यानी मीरा और महेश देशमुख के बेटे की मौत की पूरी तहकीकात अब जयदीप के हाथों में होगी. जयदीप फिल्म का नया चेहरा है, लेकिन यकीनन वह अपने रोल को आसानी से भूलने नहीं देंगे. मेकर्स ने फिल्म से उनका फर्स्ट लुक जारी कर लिखा है, अब यह केस एसरी राजवीर सिंह तोमर की टेबल पर है और इसे खोलूंगा भी मैं और बंद भी मैं करूंगा. विजय सलगांवकर के अरेस्ट के बाद. अपनी जबरदस्त और दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर एक्टर प्रकाश राज की एंट्री बताती है कि फिल्म की आखिरी किस्त बड़ा मोड़ लेने वाली है. फिल्म में प्रकाश राज वकील इंद्रजीत शेट्टी के रोल में दिखेंगे. वह अपने फर्स्ट लुक में कोट-पहने पहने पूरे रौब में दिख रहे हैं. प्रकाश राज के लिए मेकर्स कैप्शन में लिखते हैं, इंद्रजीत शेट्टी सिर्फ कानून नहीं जानता, उसे इस्तेमाल करना भी जानता है. पूरी सलगांवकर फैमिली को जेल भेज के रहूंगा.

अभिषेक पाठक ने दृश्यम- द कन्क्लूजन का निर्देशन किया है. यह सस्पेंस थ्रिलर फिल्म आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होगी. 2 अक्टूबर महज एक तारीख नहीं बल्कि फिल्म से जुड़ा सबसे बड़ा दिलचस्प झूठ भी है. बता दें, अजय देवगन की दृश्यम साउथ सुपरस्टार मोहनलाल स्टारर फिल्म दृश्यम का हिंदी रीमेक है. मोहनलाल फिल्म के तीन पार्ट पूरे कर चुके हैं और हिंदी में अब तीसरे पार्ट का रिलीज होना बाकी है. दृश्यम फ्रेंचाईजी के दर्शकों को अब 2 अक्टूबर 2026 का इंतजार लंबा महसूस हो रहा होगा.

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा की डेब्यू फिल्म का ऐलान!

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा की फिल्मों में आगमन की चर्चा लंबे वक्त से रही है। आखिरकार उनकी डेब्यू फिल्म का ऐलान हो गया है, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी साजिद खान ने उठाई है।

यह एक हॉरर-कॉमेडी होगी जिसे हीरो की हॉररिन शीर्षक दिया गया है। इसके निर्माण के लिए एकता कपूर और अमर बुटाला ने हाथ मिलाया है। जय हो मीडिया वेंचर्स प्रोडक्शन की यह फिल्म बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फिल्म की पुष्टि की है। पोस्ट के मुताबिक, फिल्म में यशवर्धन के साथ लीड रोल में नितांशी गोयल नजर आएंगी, जिन्हें लापता लेडीज (2024) से लोकप्रियता हासिल हुई थी। उनके अलावा, फिल्म में सुनीता आहूजा, जेमी लिवर, चंकी पांडे, बृजेंद्र काला और सिमरत कौर रंधावा भी हैं। यह पहला मौका होगा जब गोविंदा के बेटे और पत्नी, दोनों साथ में स्क्रीन साझा करते दिखेंगे। यशवर्धन की पहली फिल्म को अगले साल रिलीज करने की तैयारी है। यह 7 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाने के लिए उतरेगी।

इस खबर ने उन लोगों को उत्साहित कर दिया है, जो यशवर्धन के डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उधर, गोविंदा भी अपनी कमबैक फिल्म रूपा को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं, जिसमें उनके साथ कोमल रानी स्वर्णकार मुख्य किरदार में नजर आएंगी। यह कोमल रानी की डेब्यू फिल्म होने वाली है।

सीमाएं पार करने की कोशिश हो तो छोड़ देती हूं दृश्य: शुभांगी शर्मा

ओटीटी और बोल्ड सामग्री की दुनिया में काम करने वाली अभिनेत्री शुभांगी शर्मा ने मनोरंजन उद्योग में अपने अनुभवों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि बोल्ड दृश्यों की शूटिंग पर्दे पर जितनी सहज दिखाई देती है, वास्तविकता में कई बार कलाकारों के लिए उतनी ही असहज हो सकती है।

शुभांगी के मुताबिक, उद्योग में अधिकांश कलाकार और तकनीकी दल पेशेवर तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोल्ड दृश्यों की परिस्थितियों का अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कलाकार के लिए अपनी सीमाएं स्पष्ट रखना बेहद जरूरी है।

शुभांगी ने बताया कि उनका करियर सीधे बोल्ड सामग्री से शुरू नहीं हुआ था। वह पहले एक निजी कंपनी में नौकरी करती थीं। परिस्थितियों के कारण उन्हें मनोरंजन उद्योग में कदम रखना पड़ा। शुरुआत में यह उनके लिए आसान निर्णय नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने इस काम के तरीके को समझा और अपने पेशे में सहज होती गईं।

आज वह कई बोल्ड धारावाहिकों और वेब श्रृंखलाओं में काम कर चुकी हैं। अभिनेत्री का कहना है कि अब वह अपने काम को लेकर पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास महसूस करती हैं। हालांकि, उनके अनुभव में इस उद्योग में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मौजूद हैं।

बोल्ड दृश्यों की शूटिंग के दौरान सह-कलाकारों के व्यवहार को लेकर शुभांगी ने कहा कि हर कलाकार एक जैसा नहीं होता। कई कलाकार पूरी तरह पेशेवर रहते हैं और केवल दृश्य की जरूरत के अनुसार काम करते हैं। ऐसे कलाकार अपने साथी को सहज महसूस कराने और उसकी सीमाओं का सम्मान करने का पूरा प्रयास करते हैं। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग शूटिंग के माहौल का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। कभी-कभी सह-कलाकार निर्धारित निर्देशों से हटकर व्यवहार करने लगते हैं, जिससे अभिनेत्री के लिए स्थिति असहज हो जाती है।

शुभांगी के अनुसार, अंतरंग या बोल्ड दृश्यों की शूटिंग के दौरान निर्देशक कलाकारों को लगातार निर्देश देते हैं। कैमरे के सामने किस तरह खड़ा होना है, किस दिशा में देखना है और दृश्य को किस तरीके से प्रस्तुत करना है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है।

उन्होंने बताया कि कुछ सह-कलाकार कभी-कभी निर्धारित निर्देशों से अलग व्यवहार करने लगते हैं। कुछ लोग जानबूझकर बार-बार दृश्य दोहराने की कोशिश भी कर सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि कोई कलाकार जानबूझकर दृश्य को लंबा कर रहा है या तय सीमा से आगे जाने का प्रयास कर रहा है, तो वह शूटिंग के बीच में ही दृश्य छोड़ देती हैं।

अभिनेत्री ने स्पष्ट किया कि उद्योग में सभी सह-कलाकारों का व्यवहार ऐसा नहीं होता।

व्हाइट आउटफिट में रकुल प्रीत सिंह ने ढाया कहर!

बॉलीवुड की खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्रियों में शुमार रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ बेहद शानदार और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

व्हाइट कलर के इस रॉयल आउटफिट में रकुल सादगी और हॉटनेस का ऐसा तड़का लगा रही हैं कि सोशल मीडिया का पारा चढ़ गया है। उन्होंने फ्रंट-ओपन स्टाइल की क्रॉप जैकेट पहनी है, जिसकी फुल-स्लीव्स और मॉडर्न कट उन्हें एक बॉस-लेडी लुक दे रहे हैं। जैकेट पर लगा गोल्ड-टोन्ड स्टारफिश स्टाइल ब्रोच पूरे आउटफिट का मुख्य आकर्षण है, जो प्लेन व्हाइट लुक को तुरंत लग्जरी टच दे रहा है। इसके साथ रकुल ने हाई-वेस्टेड, फ्लोर-लेंथ पेंसिल स्कर्ट पेयर की है, जो उनकी परफेक्ट फिगर और बॉडी कर्व्स को बेहद खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रही है।

रकुल ने अपने इस एलिगेंट लुक को बैलेंस करने के लिए मेकअप और एसेसरीज को बेहद सटल रखा है। उन्होंने अपने बालों को मिडिल-पार्टेड रखकर सॉफ्ट वेवी स्टाइल दिया है। बालों पर हाइलाइट्स उनके ऑल-व्हाइट लुक को और उभरा हुआ बना रहे हैं।

न्यूड लिपस्टिक, सॉफ्ट स्मोकी आइज और फ्लॉलेस बेस के साथ उनका मिनिमल ग्लोइंग मेकअप रकुल के चेहरे के ग्लो को बढ़ा रहा है। कानों में स्टेटमेंट गोल्डन इयररिंग्स और उंगलियों में मिनिमल रिंग्स उनके इस लुक को कंप्लीट करते हैं।तस्वीरों में रकुल कभी शीशे के सहारे खड़े होकर तो कभी ईंटों की वॉल के आगे कॉन्फिडेंस के साथ पोज़ देती नजर आ रही हैं। उनके सिडक्टिव और एटीट्यूड-भरे पोज़ ने पूरे फोटोशूट में एक अलग जान फूंक दी है।

भवन तैयार इंटीग्रेटेड बीएड शुरू करने के लिए शासन की मंजूरी का इंतजार

नई टिहरी(आरएनएस)। फूल सिंह बिष्ट महाविद्यालय में इंटीग्रेटेड बीएड शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे छात्र-छात्राओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। महाविद्यालय प्रशासन की ओर से बीएससी बीएड और बीए बीएड शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजा गया है लेकिन निदेशालय और शासन से इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। ऐसे में इस शिक्षा सत्र में भी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को इंटीग्रेटेड बीएड में प्रवेश के लिए देहरादून या अन्य शहरों का रुख करना पड़ रहा है। टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिलों के राजकीय महाविद्यालयों में इंटीग्रेटेड बीएड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लंबगांव महाविद्यालय में इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम शुरू होने पर उक्त पर्वतीय जिलों के छात्र-छात्राओं को प्रवेश मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन शासन-प्रशासन के स्तर पर लेट लतीफी के चलते इस सत्र में प्रवेश शुरू नहीं हो पाया। गत वर्ष नवंबर 2025 में जल निगम ने 3 करोड़ 58 लाख रुपये की लागत से बीएड भवन का निर्माण पूरा कर इसे महाविद्यालय प्रशासन को सौंप दिया था। भवन तैयार होने के बाद इंटीग्रेटेड बीएड शुरू होने की उम्मीद जगी थी लेकिन अब स्वीकृति मिलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। महाविद्यालय की ओर से बीएससी बीएड और बीए बीएड की 40-40 सीटों का प्रस्ताव भेजा गया था

10 सितंबर तक सड़क नहीं बनी तो खुद शुरू करेंगे कटिंग

चमोली(आरएनएस)। विकासखंड कर्णप्रयाग के सकंड गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर आर-पार की लड़ाई का एलान किया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी यदि 10 सितंबर तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो 11 सितंबर से वे अपने निजी संसाधनों और श्रमदान से सड़क की कटिंग शुरू कर देंगे। ग्रामीणों के अनुसार सिधौंली सड़क से सकंड गांव तक करीब सात किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। इसके लिए वर्ष 2016 में स्वीकृति के बाद सर्वे किया गया था लेकिन वर्ष 2023 में अधिक पेड़ों के कटान का हवाला देकर सड़क को निरस्त कर दिया गया। आंदोलन के बाद पांच जनवरी 2026 को विधायक अनिल नौटियाल ने लोनिवि को दोबारा सर्वे के निर्देश दिए लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि वे करीब 40 वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं और आज भी पैदल आवाजाही के लिए मजबूर हैं। विधायक महीने में दो बार गांव आएं तभी उनकी पीड़ा समझ पाएंगे। ज्ञापन देने वालों में रघुवीर सिंह, महेंद्र सिंह, विजया देवी, दाताराम, नर्वदा देवी, ऊषा देवी, युद्धवीर और गजेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। इधर प्रभारी जिलाधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि सड़क निर्माण के संबंध में संबंधित विभाग से बात कर शीघ्र कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सू- दोकू क्र.055

	2			6			1	
3			4			2		
							6	
6					4			
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.54 का हल

8	7	6	9	5	1	2	3	4
1	3	9	2	8	4	5	6	7
4	5	2	3	7	6	9	1	8
2	8	5	4	6	7	1	9	3
3	1	7	8	9	2	4	5	6
6	9	4	1	3	5	7	8	2
9	4	1	6	2	8	3	7	5
7	2	8	5	1	3	6	4	9
5	6	3	7	4	9	8	2	1

हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार में चलेगा विशेष सफाई अभियान, प्लास्टिक इस्तेमाल पर होगी चालानी कार्रवाई

हरिद्वार(आरएनएस)। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में अब हरिद्वार को साफ, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक कर सभी विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने और उसकी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर कड़ी नजर रखी जाए। दुकानदार या व्यापारी प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करते मिले तो तत्काल चालानी कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायत, ग्राम पंचायतों और खंड विकास अधिकारियों को नियमित सफाई अभियान चलाने के साथ इसकी प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रखते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों, धार्मिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आमजन को भी इससे जोड़ा जाए। सभी की सहभागिता से ही स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त हरिद्वार का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बैठक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर लगातार निगरानी रखने को कहा गया। साथ ही लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और कपड़े, जूट सहित अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को अपने अधीन कार्यालयों में संचालित शौचालयों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय अध्यक्षों को नियमित रूप से इनकी मॉनिटरिंग करनी होगी। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी की ओर से तैयार प्रारूप पर कार्यालयों के शौचालयों से संबंधित पूरा विवरण ही नोडल अधिकारी स्वच्छता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि स्वच्छ हरिद्वार और प्लास्टिक मुक्त हरिद्वार अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. लालित नारायण मिश्र, जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार पंत, मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल आदि मौजूद रहे।

कुंभ मेला भत्ता स्थायी करने की मांग तेज

हरिद्वार (आरएनएस)। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने मेला अधिकारी से मिलकर सौंपा ज्ञापन हरिद्वार, संवाददाता। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं ने कुंभ मेले के लिए नियुक्त मेला अधिकारी (स्वास्थ्य) से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं और मेला भत्ता स्थायी शासनादेश के तहत दिए जाने की मांग उठाई। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौंपे ज्ञापन में कहा कि मेला क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को बिना भेदभाव के कुंभ मेला भत्ता दिया जाए और 4200 ग्रेड पे की बाध्यता समाप्त की जाए। संगठन का कहना है कि प्रत्येक अर्धकुंभ और महाकुंभ से पहले कर्मचारियों को मेला भत्ते के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि इसका स्थायी शासनादेश होना चाहिए।प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा, प्रदेश महामंत्री सुनील अधिकारी, प्रदेश संगठन सचिव छत्रपाल सिंह, उपशाखा मंत्री अजय कुमार और उपाध्यक्ष नितिन कुमार ने कहा कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर मेला भत्ता कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और शासन इस मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेंगे।

बकायादारों पर ऊर्जा निगम की कार्रवाई, 45 कनेक्शन काटे

हरिद्वार(आरएनएस)। ज्वालापुर क्षेत्र में ऊर्जा निगम ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। कटहरा बाजार और धीरवाली क्षेत्र में लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 45 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। इस दौरान कई बकायादारों के बिजली मीटर भी जब्त किए गए। अभियान के दौरान निगम की टीम ने पांच लाख रुपये का राजस्व वसूला। अधिशासी अभियंता रवि कुमार के निर्देश पर उपखंड अधिकारी अर्चना के नेतृत्व में टीम ने घरों और प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर बिजली बिलों की जांच की। लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की गई। निगम ने चेतावनी दी कि बकाया राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभियान में अवर अभियंता (राजस्व वसूली) मुकेश रवि, लाइनमैन श्रवण कुमार गिरी, संजय चौहान, मीटर रीडर अजमल अंसारी, सुशील कुमार राव, फरमान अली, अतुल कुमार, पटवारी और चमन लाल आदि शामिल रहे।

शवदाह की लकड़ियों के लिए टिन शेड की मांग

हल्द्वानी(आरएनएस)। स्थानीय शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता दीपक नौगांई ने वन निगम और प्रशासन से रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट में शवदाह के लिए रखी जाने वाली लकड़ियों को बारिश से बचाने के लिए टिन शेड बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि विद्युत शवदाह गृह बनने के बावजूद अधिकांश लोग आज भी लकड़ियों से ही नदी किनारे शवदाह करते हैं। बरसात के दौरान खुले मैदान में रखी लकड़ियां भीग जाने से अंतिम संस्कार के समय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लकड़ियों को जलाने के लिए लोगों को डीजल, केरोसीन और लीसा जैसी चीजें अपने साथ लानी पड़ती हैं, जबकि इनका उपयोग कर लकड़ियां जलाना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि यहां लकड़ियों को बारिश से बचाने के लिए वर्षों से टिन शेड बनाने की मांग की जा रही है। उन्होंने वन निगम और प्रशासन से शीघ्र एक बड़ा टिन शेड बनाने की मांग की है, ताकि लकड़ियां भीगने से बच सकें और लोगों को शवदाह के दौरान परेशानी न हो।

बेलनी पुल का सुरक्षा ऑडिट शुरू, जल्द यात्रियों के लिए खुलेगा

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। बदरीनाथ हाईवे को केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले बेलनी पुल को यातायात के लिए खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। पुल का सुरक्षा ऑडिट शुरू हो गया है और अब मंगलवार को लोड टेस्टिंग भी की जाएगी। परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पुल को आम आवाजाही के लिए खोला जाएगा।

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने एनएच के अधिकारियों के साथ बेलनी पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पुल से संबंधित शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पुल और आसपास विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह पुल केदारनाथ और बदरीनाथ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्य पर प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से समय-समय पर निगरानी की जाती रही है। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण कार्य में कुछ देरी हुई है, लेकिन प्रयास है कि केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं को इस पुल का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि बेलनी पुल के शुरू होने से नगर में यातायात दबाव भी कम होगा। वहीं लोनिवि एनएच खंड की सहायक अभियंता प्रेरणा जगूड़ी ने बताया कि सुरक्षा ऑडिट और लोड टेस्टिंग के दौरान पुल पर विभिन्न तकनीकी परीक्षण किए जाएंगे। इनमें यूपीवी, रिबाउंड हैमर और अन्य एनडीटी (नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्ट) शामिल हैं। इसके साथ ही लोड टेस्टिंग के दौरान करीब 300 टन भार क्षमता की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षण के दौरान पुल का तापमान समेत अन्य तकनीकी मानकों को भी दर्ज किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में करीब एक सप्ताह से अधिक समय लगेगा। परीक्षण सफल रहने के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

मीडिया इंचार्ज ने चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष से की मुलाकात

हमारे संवाददाता

देहरादून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उत्तराखंड की मीडिया इंचार्ज नियुक्त की गईं पंखुड़ी पाठक ने आज उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस के मीडिया एवं संचार अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की और मार्गदर्शन लिया

मीडिया इंचार्ज पंखुड़ी पाठक ने चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ-साथ उत्तराखंड कांग्रेस के दोनों सह-प्रभारियों सुरेंद्र शर्मा एवं मनोज यादव से भी मुलाकात कर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य, चुनावी रणनीति तथा मीडिया के माध्यम से पार्टी के जनसरोकारों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने को लेकर विचार-विमर्श किया। इस दौरान कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी भी उनके साथ मौजूद रहीं। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में मीडिया एवं संचार रणनीति को और अधिक प्रभावी एवं समन्वित बनाने की दिशा में यह मुलाकात महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन, मीडिया विभाग की सक्रिय भूमिका और जमीनी मुद्दों को प्रमुखता देने के साथ कांग्रेस जनता के बीच अपने संदेश को और मजबूती से पहुंचाएगी।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जनसरोकारों, भाजपा सरकार की नीतियों से प्रभावित आम जनता के मुद्दों तथा कांग्रेस की नीतियों और आगामी चुनावी एजेंडे को तथ्यों एवं मजबूती के साथ जनता के सामने रखना मीडिया विभाग की प्राथमिकता होगी। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि पंखुड़ी पाठक के अनुभव, ऊर्जा और रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रदेश में कांग्रेस के मीडिया अभियान को निश्चित रूप से नई गति और धार मिलेगी। मुलाकात के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा एवं वीरेंद्र पोखरियाल भी मौजूद रहे।

बुलेट मोटरसाईकिल बेचने के नाम पर ठगे सवा लाख रुपये

संवाददाता

देहरादून। बुलेट मोटरसाईकिल बेचने के नाम पर सवा लाख रूपये की ठगी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुंरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मालसी निवासी ओम रतन ने राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसने ओएलएक्स के माध्यम से ऑनलाईन क्लासिक बुलेट मोटरसाईकिल का विज्ञापन देखा तो उक्त नम्बर पर सम्पर्क तो उसने जीपीके माध्यम से तीन तिथियों में कुल एक लाख 26 हजार रूपये का भुगतान कर दिया। लेकिन उसके बाद न तो उसको मोटरसाईकिल नहीं मिली और न ही उसके रूपये वापस मिले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

सूखे राजनीतिक मैदान में 'संजीवनी'

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। ऐसे समय में राहुल गांधी से जुड़ा कोई बड़ा घटनाक्रम कांग्रेस के लिए मुद्दों की कमी से निकलने का रास्ता बन सकता है। भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ राहुल गांधी नहीं होंगे। चुनौती होगी उस राजनीतिक नैरेटिव की, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस तैयार कर सकती है। अगर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया तो भाजपा को हर बयान सोच-समझकर देना होगा। एक गलत राजनीतिक प्रतिक्रिया कांग्रेस को और ताकत दे सकती है। राजनीति में कई बार कानूनी कार्रवाई का असर अदालत से बाहर ज्यादा दिखाई देता है। राहुल गांधी की संभावित गिरफ्तारी भी ऐसा ही मोड़ पैदा कर सकती है। कांग्रेस इसे संघर्ष की शुरुआत बताएगी, भाजपा कानून की कार्रवाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारने की कोशिश करेगी, भाजपा संगठनात्मक ताकत से मुकाबला करेगी और उत्तराखंड इस टकराव का केंद्र बन सकता है। यही कारण है कि राहुल गांधी की संभावित गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए संजीवनी और भाजपा के लिए गले की फांस बन सकती है।

लेकिन अंतिम फैसला अदालत, कानून और संबंधित जांच प्रक्रिया के दायरे में ही होगा। राजनीतिक दल इस घटनाक्रम को किस तरह जनता के सामने पेश करते हैं, असली लड़ाई वहीं तय होगी। उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में यह मामला अब सिर्फ एफआईआर का नहीं। नैरेटिव की लड़ाई का मामला बनता दिख रहा है।

अहमदाबाद की धनगौरी बरोलिया ने सीएम धामी को भावुक पत्र के साथ भेजी राखी

संवाददाता

देहरादून। अहमदाबाद की धनगौरी बरोलिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी को भावुक पत्र के साथ राखी भेजी।

अहमदाबाद की धनगौरी बरोलिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी भेजी है। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को एक भावुक पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने पिछले वर्ष धराली में आई आपदा के दौरान मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को याद किया है। धनगौरी ने बताया कि पिछले वर्ष रक्षाबंधन के समय वह उत्तराखंड आई थीं। इसी दौरान धराली में आई बाढ़ में वह फंस गई थीं। मुख्यमंत्री धामी जब आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे और वहां फंसे लोगों से मिले, तब उन्हें भी मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला। धनगौरी ने बताया कि उस समय रक्षाबंधन करीब था। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था कि अगर उनके पास राखी हो तो वह उन्हें राखी बांध सकती हैं। उस समय उनके पास राखी नहीं थी। उन्होंने अपने दुपट्टे का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उसे ही राखी मानकर मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया। धनगौरी ने अपने पत्र में लिखा कि उसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को अपना धर्म भाई मान लिया था। उनके लिए वह मुलाकात आज भी बहुत खास है और उस पल को वह कभी नहीं भूल सकतीं। उन्होंने कहा कि धराली की उस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने वहां फंसे लोगों का हौसला बढ़ाया और उन्हें भरोसा दिया।

धनगौरी ने भगवान श्रीकृष्ण और द्रौपदी के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह श्रीकृष्ण द्रौपदी की मदद के लिए आगे आए थे, उसी तरह मुख्यमंत्री भी उस कठिन समय में उनके लिए सहारा बने। धनगौरी ने कहा कि इस वर्ष वह अहमदाबाद में हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी भेजना वह नहीं भूल सकतीं। इसी भाव के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के लिए राखी भेजी है।

पत्र के अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कामना की और कहा कि वह इसी तरह उत्तराखंड और प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें। धराली की आपदा के दौरान दुपट्टे के टुकड़े से शुरू हुआ यह भाई-बहन का रिश्ता आज भी धनगौरी के लिए उतना ही खास है।

छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी

संवाददाता

देहरादून। छात्र हितों से जुडी विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा।

आज यहां डीबीएस पीजी कॉलेज, देहरादून में छात्रहित से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। तीन दिन बीत जाने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की मांगों पर अब तक कोई ठोस एवं संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। छात्रसंघ अध्यक्ष हर्ष मोहन राणा ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांगों पर स्पष्ट एवं सकारात्मक निर्णय नहीं लेता, तब तक छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि समस्त छात्रहितों की लड़ाई है। छात्र अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करते रहेंगे और मांगें पूरी होने तक धरने से पीछे नहीं हटेंगे। इस धरना प्रदर्शन में छात्र नेता अभिनव कफलिया के साथ मुकेश बसेरा, दीपांशु भंडारी, अमन, आर्यन, वैभव, दक्ष एवं राजीव सहित अनेक छात्र उपस्थित रहे। तीन दिन बीत गए, लेकिन संघर्ष अभी जारी है जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, धरना जारी रहेगा।

मसूरी गोलीकाण्ड के शहीदों को याद किया

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी संयुक्त परिषद ने मसूरी गोलीकाण्ड के शहीदों को याद कर उनको श्रद्धांजलि दी।

आज यहां उत्तराखंड आन्दोलनकारी संयुक्त परिषद ने 2 सितम्बर 2026 को शहीद स्थल सभागार, देहरादून में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर 1994 के मसूरी गोलीकाण्ड के शहीदों तथा वरिष्ठ आन्दोलनकारी स्वर्गीय वेदप्रकाश शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 2 सितम्बर 1994 को खटीमा गोलीकाण्ड के विरोध में मसूरी के झूलाघर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे आन्दोलनकारियों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने गोलियां चला दी थीं। इस घटना में छह आन्दोलनकारी शहीद हो गए थे, जिनमें बेलमती चौहान और हंसा धनाई जैसी वीरांगनाएं भी शामिल थीं। अन्य शहीदों में बलबीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी और मनमोहन ममगई शामिल हैं। इस गोलीबारी में तत्कालीन सीओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई थी। सभा का एक प्रमुख उद्देश्य हाल ही में दिवंगत हुए वेदप्रकाश शर्मा को याद करना भी था। वे उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के एक प्रमुख स्तंभ एवं उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष थे। आन्दोलनकारियों के अधिकारों और राज्य की मांगों को लेकर उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए राज्य आन्दोलनकारियों की लंबित मांगों को उठाने की बात कही। इन मांगों में राज्य, छूटे हुऐ आन्दोलनकारियों को चिन्हित करना, राज्य आन्दोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी घोषित करना, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना तथा एक समान पेंशन दिलाना शामिल है। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण इन्हीं शहीदों की शहादत की बदौलत हुआ है और इसलिए उनके सपनों को साकार करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आन्दोलनकारी और उनके परिजन उपस्थित थे। इस अवसर पर संरक्षक बालेश बबानिया, जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार, वरिष्ठ राज्य आन्दोलनकारी जब्बर सिंह पावेल, अनन्त आकाश, चिन्तन सकलानी, राजेश शर्मा (सुपुत्र स्व वेदप्रकाश शर्मा), सतीश धौलाखण्डी, जयदीप सकलानी, प्रभात डंडरियाल, अम्बुज शर्मा, लोक बहादुर थापा, तरूण कुमार, गीतादेवी, सुभागा फरस्वाण, दुर्गाध्यानी, सेमवाल, मुकेश मोगा, पुष्पलता वैश्य, राजदुलारी लोधी, कल्पेश्वरी नेगी, जगदेश्वरी अन्थवाल, सरिता सिलमाना, शान्ति बुटोला, कमलादेवी, विकास रावत, सत्येंद्र बुटोला, निशा मस्ताना, जमुना देवी, शिवप्रसाद भट्ट, रामभरोसे भट्ट, गीता, सीमा आदि बडी संख्या में आन्दोलनकारी उपस्थित थे।

ऊधमसिंह नगर में बिना मान्यता संचालित चार मदरसे सील

संवाददाता

ऊधमसिंह नगर। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में लागू नई व्यवस्था के तहत प्रशासन ने बिना आवश्यक मान्यता एवं दस्तावेजों के संचालित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए चार मदरसों को सील कर दिया।

आज यहां उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में लागू नई व्यवस्था के तहत प्रशासन ने बिना आवश्यक मान्यता एवं दस्तावेजों के संचालित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में ऊधमसिंह नगर जिले के बाजपुर परगना क्षेत्र में चार मदरसों को सील किया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम बाजपुर ऋचा सिंह और कोतवाली निरीक्षक नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ सीलिंग की कार्रवाई की गई।

प्रशासन के अनुसार, संबंधित मदरसा संचालक निरीक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा सील किए गए मदरसों में मदरसा जामिया हनफिया रजाउत उलूम, बाजपुर, मदरसा गुलशने इस्लाम, कनोरा, मदरसा

जामिया फातिमा, बाजपुर, तथा मदरसा मोइनुल उलूम, मोहल्ला गांधीनगर, केलाखेड़ा-बाजपुर शामिल हैं। एसडीएम ऋचा सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र में संचालित मदरसों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिन संस्थानों के पास निर्धारित मान्यता अथवा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अन्य मदरसों की भी जांच-पड़ताल जारी है। वहीं, राज्य में लागू नई मदरसा शिक्षा व्यवस्था और मान्यता संबंधी प्रावधानों के खिलाफ कुछ मदरसा संचालकों की ओर से नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण तथा शिक्षा बोर्ड से मान्यता की अनिवार्यता के चलते कई मदरसों के सामने संचालन संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को प्रस्तावित है। ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि शासन के निर्देशों के तहत जिले में मदरसों का निरीक्षण अभियान जारी है। जिन संस्थानों ने निर्धारित प्राधिकरण से मान्यता नहीं ली है अथवा आवश्यक मानकों और नियमों का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने कहा कि नई व्यवस्था की मूल भावना बच्चों को उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान से जोड़े रखते हुए उन्हें आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराना और शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा आधुनिक पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत मदरसों को भी निर्धारित शैक्षणिक मानकों और नियमों का पालन करना होगा। जो संस्थान निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, जो बच्चों को आधुनिक एवं मुख्यधारा की शिक्षा से दूर रखे। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी उद्देश्य से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत बच्चों को उनकी सांस्कृतिक एवं धार्मिक जड़ों से जुड़े रहने के साथ-साथ विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, कौशल विकास और अन्य आधुनिक विषयों की शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश में संचालित होने वाले सभी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन करना होगा। सरकार का स्पष्ट मत है कि जो संस्थान नियमों के अनुरूप संचालित होंगे, उन्हें व्यवस्था के तहत कार्य करने का अवसर मिलेगा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य सचिव ने दीपेन्द्र चौधरी को दिलायी आयुक्त पद की शपथ

संवाददाता

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में दीपेन्द्र चौधरी को उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में आयुक्त पद के लिए पद की शपथ दिलाई। आज यहां मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में दीपेन्द्र चौधरी को उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में आयुक्त पद के लिए पद की शपथ दिलाई।

मुख्य सचिव ने दीपेन्द्र चौधरी को नवीन दायित्व के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। दीपेन्द्र चौधरी ने शपथ ग्रहण के पश्चात कहा कि वे आयोग द्वारा सौंपे गए दायित्वों का पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करेंगे तथा नागरिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य को और प्रभावी बनाने के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय सहित शासन एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

फायरिंग की घटना का खुलासा, तमंचे सहित एक गिरफ्तार

◆होटल स्वामी से खाने-पीने के विवाद को लेकर थी रंजिश

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लया है। जिसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया है। आरोपियों ने होटल मालिक पर पुरानी रंजिश के चलते ही फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि मामले के अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार बीती 24 अगस्त को बेड़पुर कलियर निवासी सुहेब ने त्यागी ढाबा निकट बेड़पुर चौक के पास किन्ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता के ऊपर जान से मारने की नीयत से तंमचे से फायर करने व जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो जाने

के संबंध में तहरीर दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी।

जांच के दौरान घटना में प्रकाश में आये आरोपी विशु सैनी पुत्र अरुण कुमार निवासी ग्राम गुम्मावाला थाना पिरान कलियर जनपद हरिद्वार को खादर वाली रोड़ से हिरासत में लेकर उसकी निशांदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा 12 बोर बरामद किया। पकड़े गए आरोपी के अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है।

कुम्भ मेला-2027: यातायात नियंत्रण उपसमिति की बैठक आयोजित

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। कुम्भ मेला-2027 को सकुशल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा एसएसपी नवनीत सिंह की अध्यक्षता में मार्च 2026 में यातायात नियंत्रण उपसमिति गठित की गई। इसी क्रम में आज कुम्भ मेला-2027 के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, संभावित यातायात दबाव एवं चुनौतियों का पूर्व आकलन करने तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में परामर्श एवं सहायता हेतु हरिद्वार मे एसएसपी नवनीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

समिति में देहरादून, ऋषिकेश एवं टिहरी के संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ धर्मशाला, अखाड़ा, होटल, आश्रम, टैक्सी संचालक, रोडवेज, रेलवे मुरादाबाद, परिवहन विभाग सहित विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारी/प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है।

समिति द्वारा सभी संबंधित विभागों एवं स्टैक होल्डरों के बीच बेहतर समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करते हुए कुम्भ मेले के दौरान यातायात को सुचारु, सुरक्षित एवं बाधामुक्त बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बैठक में कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन हेतु निर्धारित किए जाने वाले पैदल मार्गों की विस्तृत समीक्षा की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैदल मार्गों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाए जाने तथा भीड़ नियंत्रण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।